

राजधानी रायपुर के युवाओं में दिखा जोश
जयस्तंभ चौक पर उमड़ी क्रिकेट प्रेमियों की भीड़



छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचारहीनहीं, विचार भी

17 साल इंतजार, फिर
लगातार दो ट्रॉफी, गुजरात
को पांच विकेट से हराया

सोने का
सच्चा भाव
आनंद का सच्चा भाव

18 केरट रेड = **₹114621/-**
(75.00%)

22 केरट रेड = **₹139990/-**
(91.60%)

24 केरट रेड = **₹152813/-**
(99.99%)

सोने का भाव" प्रति 10 ग्राम | GST Extra

ANAND
Jewels
Pandri, Raipur

आरसीबी
161/5 (18)
जीटी
155/8(20)

प्लेयर ऑफ द मैच
विराट कोहली
75 रन नाबाद
42 गेंद
9 चौके
03 छक्के

एजेसी ►► अहमदाबाद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने आईपीएल 2026 के फाइनल में किंग कोहली के दम पर गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा। 156 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत संतुलित रही। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और टीम की जीत की नींव रखी। आरसीबी ने 18 ओवर में पांच विकेट खोकर 161 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया।

कोहली के दम पर लगातार दूसरी बार आरसीबी चैंपियन

लगातार दूसरी बार जीता खिताब

आरसीबी ने 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतकर 18 साल के इंतजार को खत्म किया था। इसके बाद 2026 में लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतकर टीम ने अपनी बाढ़साहत कायम रखी। आईपीएल इतिहास में यह आरसीबी का दूसरा खिताब है।



वैभव के नाम रही ऑरेंज कैप - 779 रन प्राइज मनी - 10 लाख रुपए	रखड़ा के नाम रही पर्पल कैप - 29 विकेट प्राइज मनी - 10 लाख रुपए
--	---

करोड़ों की प्राइज मनी

- ट्रॉफी जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी
- फाइनल में हारने वाली गुजरात टाइटंस को भी मिले 13 करोड़ रुपए
- सनराइजर्स हैदराबाद टेबल में तीसरे पायदान पर रही, उसे 7 करोड़ रुपए मिले
- चौथे पायदान की राजस्थान को 6.5 करोड़ रुपए की रकम मिली



चंबा जाते वक्त कार खाई में गिरी, बेंगलूर में रहते थे मृतक

हिमाचल में भिलाई के एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत

- मृतक के पिता व परिवार भिलाई निवासी
- खबर लगने पर परिजन रवाना हुए

हादसे में पूरा परिवार 'विदा', मां-बाप समेत दो बच्चों की मौत



हरिभूमि न्यूज़ ►► भिलाई

हिमाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में भिलाई निवासी एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतक बेंगलूर में काम करता था। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ घूमने के लिए गया था। शुक्रवार की रात इनोवा कार में बर्फ बारी देखने के लिए चंबा के लिए निकले थे कि रास्ते में इनोवा कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर परिजन हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा हिमाचल ►►शेष पेज 6 पर

ह्यूमैन चैन बनाकर शव को निकाला

हिमाचल की एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और चैन बनाकर एक-एक के शव को रस्सियों के सहारे खाई से बाहर निकाला। शव का पोस्टमॉर्टम होने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों से संपर्क कर हादसे की जानकारी दी। हिमाचल पुलिस ने हादसे की जानकारी दुर्गम पुलिस को भी दी है। मृतक परिवार के पिता बीएसपी से सेवानिवृत्त मरोदा में रहते हैं।

सात पर्यटक और एक टैक्सी चालक की मौत

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक खाई में कार के गिर जाने से मारे गए सात पर्यटकों और एक टैक्सी चालक के शवों को निकालने का अभियान रविवार को जारी रहा। मृतकों में चार भिलाई निवासी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह घटना शुक्रवार देर रात चुराह उपमंडल के बैरागढ़-साव पास किल्लर मार्ग पर हुई लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी शनिवार दोपहर को मिली। अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना उस वक्त हुई जब कार हिमाचल प्रदेश के सबसे दुर्गम मार्गों में से एक, बर्फ से ढके साव दर्रे की ओर जा रही थी। चुराह से भाजपा विधायक हंस राज ने बताया कि शवों को निकालने का अभियान जारी है।

मटेरियल के दाम में 15 से 40 फीसदी तक का इजाफा

मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना हुआ महंगा



हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है। मध्यम वर्ग का इंसान चाहता है कि उसका खुद का आशियाना कम से कम दाम में बन जाए, लेकिन इस समय युद्ध के कारण हर सेक्टर के सामानों के दाम में आग लग गई है। इसके कारण अपना घर बनाना बहुत महंगा हो गया है। कुछ सेक्टरों ने तो मोका का फायदा उठाते हुए भी दाम बढ़ा दिए हैं।

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की आग में अपना आशियाना भी झुलस गया है। अब मध्यम वर्ग के लिए घर बनाना भी बहुत महंगा हो गया है। जो हजार वर्गफीट का घर पहले 19 लाख तक में बन जाता था, वह अब 23 लाख में बन रहा है। ऐसे में चार लाख रुपए ज्यादा लग रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि हर तरह का मटेरियल महंगा हो गया है।

सरिया, सीमेंट के दाम बढ़े

घर बनाने के काम में आने वाले सरिया और सीमेंट के दाम भी आसमान पर चले गए हैं। जो सरिया युद्ध के पहले 50 हजार रुपए टन था, उसके दाम इस समय 60 हजार से ज्यादा हो गए हैं। सीमेंट के दाम तो कंपनियों ने अपनी मर्जी से बढ़ा दिए हैं। इसके दाम में 30 रुपए तक का इजाफा हो गया है। इसके दाम और बढ़ने की तैयारी चल रही है। रेत, गिट्टी, ईंट के दाम भी 15 से 20 फीसदी बढ़ गए हैं।

सबसे ज्यादा असर बिजली के तारों पर पड़ा है। इसके दाम 30 से 40 फीसदी बढ़ गए



बिजली का सामान बहुत महंगा

बिजली का सामान इस समय बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। सबसे ज्यादा असर बिजली के तारों पर पड़ा है। इसके दाम 30 से 40 फीसदी बढ़ गए हैं। पहले मटेरियल सहित 19 सौ रुपए में ठेकेदार काम करते थे, अब इसकी कीमत 2250 से 23 सौ रुपए हो गई है। इसी तरह से चार ►►शेष पेज 6 पर

चार सौ का इजाफा

मटेरियल महंगा होने के कारण घर बनाने की लागत में अब 400 रुपए फीट का इजाफा हो गया है। पहले मटेरियल सहित 19 सौ रुपए में ठेकेदार काम करते थे, अब इसकी कीमत 2250 से 23 सौ रुपए हो गई है। - विजय नन्थानी, बिल्डर

रंग, पेंट महंगा

रंग और पेंट के दाम में भी भारी इजाफा हो गया है। इसके दाम भी 20 से 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं। अक्सर कंपनी का जो पेंट पहले 200 रुपए लीटर आता था, उसके दाम 250 रुपए लीटर हो गए हैं। 400 रुपए लीटर वाले पेंट के दाम 500 रुपए और 800 रुपए वाले पेंट के दाम 1000 रुपए हो गए हैं। अन्य रंग-रोगन का दूसरा मटेरियल भी 15 से 20 फीसदी महंगा हो गया है। सेनेटरी का सामान भी 20 फीसदी तक महंगा हुआ है।

टाइल्स, विंडो दरवाजे महंगे

गुजरात के मोरबी में सबसे ज्यादा टाइल्स का उत्पादन होता है। एलपीजी गैस न मिलने के कारण यहां के पांच सौ से ज्यादा प्लांट बंद हो गए हैं। ऐसे में अपने प्रदेश में भी टाइल्स की सप्लाई नहीं के बराबर हो रही है। टाइल्स की कीमत भी 20 से 25 फीसदी बढ़ गई है। टाइल्स न मिलने से घर बनाने का काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन ज्यादा कीमत में किसी तरह से लोग टाइल्स लेकर अपना घर बना रहे हैं तो इनका बजट बिगड़ गया है। टाइल्स पहले 60 रुपए फीट में मिलती थी, उसके दाम 75 से 80 रुपए हो गए हैं। कम कीमत वाली 40 रुपए फीट वाली टाइल्स के दाम 50 से 55 रुपए हो गए हैं। इसी के साथ स्टील और प्लास्तीक के विंडो के दाम 20 फीसदी तक बढ़े हैं। लकड़ी के दरवाजों के दाम भी 15 फीसदी तक ►►शेष पेज 6 पर

फ्रेंच ओपन: दिग्गजों की कब्रगाह बनता रोलां गैरो

पेरिस से डॉ. हिमांशु द्विवेदी



जैसे मुट्ठी में रेत को लंबे समय तक संभालकर रखना बेहद कठिन होता है, वैसे ही टेनिस की दुनिया में रेत के मैदान पर अपनी बादशाहत कायम रखना भी असाधारण चुनौती है। इसीलिए क्ले कोर्ट को टेनिस जगत की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। राफेल नडाल और ब्योन बोर्गे ही इस नियम के अपवाद थे, जिन्होंने वर्षों तक फ्रेंच ओपन पर ऐसा आधिपत्य



के धैर्य, संयम, एकाग्रता, शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक दृढ़ता और तकनीकी कुशलता की कठोर परीक्षा लेता है। यहां गति से कहीं अधिक महत्व धैर्य का है। हार्ड कोर्ट और घास के मैदानों पर अपनी विस्फोटक सर्विस से प्रतिद्वंद्वी को असहाय कर देने वाले खिलाड़ी यहाँ अक्सर एक-एक अंक के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। क्ले कोर्ट पर गेंद टप्पा खाने के बाद अपनी गति खो देती है, रैलियां लंबी हो जाती हैं और अंक जीतने के लिए बार-बार नए अवसर बनाने पड़ते हैं। ऐसे में पैरों की चपलता, कोर्ट कवरेज और मानसिक दृढ़ता ही खिलाड़ी की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।

जहाँ अन्य ट्रूनामेंटों में कई मुकाबले अपेक्षाकृत तेजी से समाप्त हो जाते हैं, वहीं फ्रेंच ओपन में पाँच सेट तक चलने वाली थकाऊ लड़ाइयाँ सामान्य बात हैं। यही कारण है कि यहां केवल कोशल नहीं, बल्कि सहनशक्ति और मानसिक शक्ति भी निर्णायक भूमिका निभाती है। पिछले वर्ष का फाइनल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, जब यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज के बीच ग्रैंड स्लैम इतिहास की सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक खेला गया। जो पांच घंटे से भी ज्यादा समय तक चला था। कई बार ऐसा लगा कि मैच सिनर की मुट्ठी में है, लेकिन अल्काराज ने असाधारण जुझारूपन दिखाते हुए हार के कगार से वापसी की और अंततः खिताब ►►शेष पेज 6 पर

सीएम ने दुर्ग को दी 739 करोड़ की सौगात

सुशासन का लक्ष्य

251 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन

दुर्ग। स्वर्गीय झारुआ देवांगन शासकों बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान में सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिबिर आयोजित किया गया। शिबिर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दुर्ग जिले को 739 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 251 लोककल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया।

प्रदीप सोनी हत्याकांड में मिले अहम सुराग

जंगल में मिले सामान की मदद से आरोपियों तक पहुंचेगी पुलिस

हरिभूमि न्यूज़ ►► पेंड्रा

सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर जंगल क्षेत्र से जला हुआ और ►►शेष पेज 6 पर

व्यापारी की हत्या

गोएतलब है कि पेंड्रा के कोटमी साप्ताहिक बाजार में मंगलवार शाम को सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं।

दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में जल्द देगा दस्तक

छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले तीन से चार दिन में दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल तट पर दस्तक देगा। पहले अनुमान लगाया गया था कि 26 मई को तय समय से पहले मानसून के आने की संभावना है, लेकिन बाद में यह लेट हो गया। अब अगले तीन दिनों में यह केरल पहुंच सकता है। वहीं, देश में एक बार फिर से आंधी और बारिश का प्रहार होने वाला है। आईएमडी की भविष्यवाणी के मुताबिक 1 जून ►►शेष पेज 6 पर

यहां अलर्ट

बारिश-आंधी के चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को देश के 19 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में आंधी और मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेंगी। वहीं, पूर्वी राज्यों को लोगों के लिए खास चेतावनी है।



रविवार को दिल्ली और आसपास इलाकों में हुई बारिश।

सामान्य से कम बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मौसम के दौरान सामान्य वर्षा होने की संभावना है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बयान में कहा, देश के अधिकतर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों वाले मानसून कोर जोन में दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा सामान्य से कम (एलपीए के 94 प्रतिशत से कम) रहने की सबसे अधिक संभावना है।

रुक-रुक कर चली केदारनाथ यात्रा

मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, आंधी-तूफान और प्रतिकूल मौसम की आशंका जताई है। मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने घटियातयन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। दोपहर बाद मौसम ठीक होने पर यात्रियों को फिर आगे भेजा गया। रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि बारिश रुकने और मौसम में सुधार होने के बाद केदारनाथ ट्रेकिंग मार्ग पर वीथ्यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। खराब मौसम के कारण अलग-अलग चेकपॉइंट पर सुरक्षित रूप से रोके गए तीर्थयात्रियों को अब आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में रविवार को बेमेतरा विधायक दीपेश साहू अन्य जोड़ों के साथ विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में 23 जोड़ों ने वैदिक रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। समारोह को विशेष पहचान विधायक दीपेश साहू के विवाह ने दिलाई।



रायपुर। अभनपुर थाना क्षेत्र के कोलार स्थित कल्पवृक्ष रिसोर्ट में खोखी जिमखाना क्लब में अवैध रूप से कैसीनो संचालित होने की सूचना पर ग्रामीण एसपी श्वेता सिन्हा के निर्देशन में पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा शनिवार को संयुक्त कार्रवाई की गई। क्लब में पोकर काइस टेबल और रमी खेलने के लिए ताश की पती और टेबल मिली, जिसे सफल किया गया है और संचालकों को संचालन से संबंधित समस्त दस्तावेज पेश करने कहा गया है। क्लब महासमुंद निवासी किसी प्रशस्त अग्रवाल तथा उसके साथी राजेश द्वारा संचालित किए जाने की बात सामने आई है। क्लब संचालक जब तक वैध दस्तावेज पेश नहीं करेंगे, तब तक क्लब सील रहेगा।



रायपुर। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में तथा पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में पुलिस कमिश्नरेट रायपुर में अर्बन पुलिसिंग प्रशिक्षण संचालित है। आज इस प्रशिक्षण में सम्मिलित प्रशिक्षार्थियों का आकर्षक मार्चपास्ट एवं प्रशस्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ। कार्यक्रम में राज्य के 25 जिलों से आए 247 पुरुष नव आरक्षक एवं 47 महिला नव आरक्षक के साथ ही रायपुर जिले के 22 नवनियुक्त नव आरक्षक भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ में नव आरक्षकों ने अनुशासन, समन्वय, उमंग तथा उत्साह के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय देते हुये आकर्षक मार्चपास्ट प्रस्तुत किया । इस मार्च पास्ट में 11 प्लाटून जिनमें 8 पुरुष एवं 3 महिला प्लाटून सम्मिलित थे, जिन्होंने अपने प्रभावशाली परेड प्रदर्शन कर उपस्थित अधिकारियों एवं अतिथियों का ध्यान आकर्षित किया।

वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी रायपुर। वन विभाग में वनरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में सरस्वती नगर थाने की पुलिस ने जालसाज दीपराज गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। जालसाज ने बलौदाबाजार जिले के युवक प्रकाश कुमार ठाकुर को वन विभाग में सीधी भर्ती कराने का झांसा दिया और करीब एक वर्ष तक अलग-अलग किस्तों में 11 लाख रुपए वसूल लिए। विश्वास दिलाने के लिए उसने वनरक्षक पद पर नियुक्ति का फर्जी आदेश पत्र भी तैयार कर पीड़ित को सौंप दिया। जब पीड़ित ने विभाग में दस्तावेज की जांच कराई, तो पूरा मामला फर्जी निकला।

विधायक दीपेश भी बने वर, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 23 जोड़ों ने लिए सात फेरे

हरिभूमि न्यूज ►► बेमेतरा

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के मंच पर आम नवयुगलों के साथ विधायक का विवाह सामाजिक समानता और सादगी का संदेश देता नजर आया। विवाह संस्कार के दौरान सभी नवदंपतियों को शासन की ओर से निर्धारित सहायता राशि और उपहार भी प्रदान किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने बेमेतरा पहुंचे, लेकिन अचानक बदले मौसम और कार्यक्रम की परिस्थितियों के कारण वे मुख्य समारोह स्थल तक नहीं पहुंच सके। बाद में उन्होंने जिला

मुख्यालय स्थित विश्राम गृह में नवविवाहित जोड़ों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। आयोजन का सबसे आकर्षक दृश्य विधायक दीपेश साहू की पारंपरिक छत्तीसगढ़ी शैली में निकली बारात रही। दूल्हे के रूप में विधायक बैलगाड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पहुंचे। बैलगाड़ी की कमान स्वयं उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने संभाली। बारात में जनप्रतिनिधियों, भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी संख्या शामिल हुई। छत्तीसगढ़ी लोकधुनों पर नृत्य और पारंपरिक माहौल ने पूरे आयोजन को उत्सवी स्वरूप प्रदान किया।



शनिवार को एयर इंडिया की फ्लाइट दो कोशिशों के बाद भी रायपुर में नहीं हो सकी लैंड मौसम ने बिगाड़ा हवाई सफर, दिल्ली से आने वाले नागपुर में अटके, सुबह ट्रेन और बस से पहुंचे रायपुर



आए दिन बदलते मौसम के मिजाज ने हवाई सफर का गणित बिगाड़ दिया है। शनिवार को राजधानी में चली आंधी ने एयर इंडिया की दिल्ली-रायपुर फ्लाइट को दो कोशिशों के बाद भी लैंड नहीं होने दिया। यात्री नागपुर में अटके रहे और बाद में ट्रेन तथा बस के माध्यम से रायपुर पहुंचे। इस फ्लाइट से वापस दिल्ली जाने वाले यात्री रायपुर में इंतजार करते रहे। सुबह उन्हें नागपुर से भेजी गई दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया।



शनिवार की शाम अचानक राजधानी समेत माना इलाके का मौसम बदला। इस दौरान राजधानी की तुलना में माना इलाके में करीब साठ किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। इसका असर शाम को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में लैंड होने वाली तीन फ्लाइट पर हुआ था। सबसे ज्यादा प्रभावित एयर इंडिया की एआई 1718-1811 के रायपुर-दिल्ली-रायपुर के यात्री हुए। अपने निर्धारित समय पर यह फ्लाइट रायपुर पहुंची तो सही, मगर हवा की तेज गति के कारण लैंड नहीं हो पाई और उसे नागपुर भेज दिया गया। करीब डेढ़ घंटे बाद फ्लाइट पुनः सफर कर रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची, मगर एटीसी से लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। एयरक्राफ्ट पुनः नागपुर पहुंचा और काफी इंतजार के बाद यात्रियों को नीचे उतारा गया। करीब ढाई बजे फ्लाइट के यात्रियों बताया गया कि

इस उड़ान को रद्द कर दिया गया है और उनके लिए बस का इंतजाम किया जा रहा है। यात्री चाहें तो अपने फ्लाइंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बस छूटने की टाइमिंग तय नहीं होने के कारण ज्यादा यात्रियों ने ट्रेन का सहारा लिया और रविवार की सुबह रायपुर पहुंचे। इतना ही नहीं, इस फ्लाइट से

अपनी दिल्ली की उड़ान पूरी करने वाले यात्री देर रात एयरपोर्ट पर ही अटके रहे। काफी देर बाद उन्हें बताया कि उनके लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की गई है। शनिवार की संशोधित फ्लाइट 10.25 बजे रायपुर आकर सुबह 11.05 बजे यात्रियों को लेकर दिल्ली रवाना हुई।

बिजली नियामक आयोग में चल रहा मंथन लगेगा महंगी बिजली का झटका, इस माह नया टैरिफ जारी करने की तैयारी



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

प्रदेशभर के बिजली उपभोक्ताओं को इस माह जून से महंगी बिजली का झटका लग सकता है। नए सत्र के लिए बिजली का नया टैरिफ जारी करने की बिजली नियामक आयोग में तैयारी चल रही है। जून में कभी भी इसको जारी किया जा सकता है। आयोग तय करेगा कि नया टैरिफ जून से लागू होगा या फिर अगले माह जुलाई से। टैरिफ पर फैसला करने में इसलिए विलंब हो रहा है, क्योंकि आयोग में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनियों ने अपने आने वाले चार साल का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इसका आकलन करने में ज्यादा समय लग रहा है। इसी के साथ नए सत्र के लिए 63 सौ करोड़ घाटे की याचिका के कारण भी इसके मंथन में विलंब हो रहा है। नियमों के मुताबिक जब पॉवर कंपनी नए सत्र के लिए टैरिफ का लेखा-जोखा नियामक आयोग में देती है तो उसको चार साल के खर्च का हिसाब देना रहता है। एक बार चार साल का लेखा-जोखा देने के बाद फिर हर साल चार साल का लेखा-जोखा देने की जरूरत नहीं होती है।

इस तरह हर साल बढ़ेगा खर्च

पॉवर कंपनी ने अपनी याचिका में बताया है कि उसको 2026-27 के लिए 25460.30 करोड़ के राजस्व की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा 21150.81 करोड़ का खर्च बिजली खरीदने पर होगा। इसी के साथ 3250.34 करोड़ संभारण एवं संधारण का खर्च है। 1429.50 करोड़ का ब्याज, 1116.15 करोड़ अन्य व्यय होगा। इसके बाद 2027-28 में बिजली खरीदी पर 22437.96 करोड़ का खर्च होगा। इसके बाद 3614.89 करोड़ संभारण एवं संधारण खर्च, 1259.58 करोड़ अन्य खर्च और 518.27 करोड़ का खर्च ब्याज पर होगा। इस सत्र में कुल 27306.02 करोड़ का खर्च होगा। 2028-29 में 24964.63 करोड़ का खर्च बिजली खरीदी पर होगा। संभारण एवं संधारण का खर्च भी बढ़कर 3940.21 करोड़ होगा। अन्य खर्च जहां 1381.35 होगा वहीं ब्याज पर 587.62 करोड़ लगेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर 30307.93 करोड़ के राजस्व की जरूरत होगी। इसी तरह से 2029-30 के सत्र में सबसे ज्यादा 27179.48 करोड़ का खर्च बिजली खरीदी पर लगेगा।

63 सौ करोड़ घाटे की याचिका

पॉवर कंपनी ने नए सत्र 2026-27 के लिए पूरा लेखा-जोखा बनाकर नियामक आयोग में नए टैरिफ के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका में बताया गया है कि प्रचलित दर से 26216 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना है। इसी के साथ साल भर का खर्च 25460 करोड़ बताया गया है। ऐसे में 756 करोड़ का फायदा होगा। लेकिन इसी के साथ पिछले सत्रों की अंतर की कारण का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि नए सत्र के फायदे को पुराने अंतर की राशि में कम करने के बाद भी 63 सौ करोड़ के राजस्व की और जरूरत होगी। नए सत्र में 26 सौ करोड़ का राजस्व मिलेगा पुराना घाटा 63 सौ करोड़ है, ऐसे में नए सत्र के लिए कुल 32 हजार पांच सौ करोड़ से ज्यादा के राजस्व की जरूरत बताई गई है। इस जरूरत के हिसाब से ही नया टैरिफ तय करने की मांग रखी गई है।

सोने के झुमके गिरवी रख 1.5 लाख गबन करने वाली महिला गिरफ्तार

जगदलपुर। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सोने के झुमके गिरवी रखकर लगभग 1.5 लाख रुपये गबन करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के वापस जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने वर्ष 2024 में अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसें की आवश्यकता होने पर सोने के झुमके सूरज नागवानी को तौल करवाने के लिए दिए थे, ताकि उनकी बिक्री से राशि प्राप्त की जा सके। सूरज ने अपनी मां नीतू नागवानी के साथ मिलकर उक्त झुमकों को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख दिया और प्राप्त राशि का स्वयं उपयोग कर लिया। प्रार्थी ने अपने झुमके वापस मांगे, तो आरोपियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया और न तो झुमके लौटाए, न ही पैसे दिए। मामले की शिकायत कोतवाली थाना में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पृष्ठताछ के दौरान आरोपी नीतू नागवानी लगातार गुमराह करती रही और साक्ष्य छुपाने के साथ-साथ विवेचना में सहयोग नहीं किया।

दिल्ली और रायपुर एम्स के डाक्टरों ने पहली बार मिलकर रोबोटिक सर्जरी को दिया अंजाम

गंभीर ऑपरेशन को अधिक सटीकता और कम जोखिम के जरिए पूरा किया जा रहा

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

पेट दर्द की समस्या लेकर आए मरीज के इलाज के लिए स्थानीय एम्स के डाक्टरों ने दिल्ली एम्स के चिकित्सकों के साथ मिलकर रोबोटिक सर्जरी को अंजाम दिया। अथेड के इलाज के लिए रोबोटिक-असिस्टेड कोलेसिस्टेक्टोमी (पित्ताशय निष्कासन) की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान दोनों संस्थानों के बीच ऑपरेशन की रणनीतियों, तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। रायपुर, दिल्ली समेत देश के कुछ एम्स आने वाले मरीजों को रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे रहे हैं। रोबोट की मदद से मरीजों के गंभीर ऑपरेशन को अधिक सटीकता और कम जोखिम के



जरिए पूरा किया जा रहा है। इसी दौरान पहली बार दोनों संस्थानों के चिकित्सकों की टीम ने मिलकर 47 साल के मरीज की स्टोन से संबंधित समस्या का समाधान रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से पूरा किया। यह प्रक्रिया रियल-टाइम टेलीप्रेंजेस तकनीक की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जिसके माध्यम से देश के अग्रणी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच दूरस्थ शल्य सहयोग, ऑपरेशन के दौरान मार्गदर्शन तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान संभव हुआ।

स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य तकनीकी प्रगति पर

एम्स रायपुर के कार्यपालक निदेशक अशोक जिंदल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का भविष्य केवल तकनीकी प्रगति पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि संस्थान अपनी नैदानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए किस प्रकार प्रगामी सहयोग स्थापित करते हैं। जनरल सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं हिमागढ्यक्ष डॉ. देवज्योति मोहंती ने कहा कि यह सहयोग ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं नैदानिक मंच सिद्ध हुआ है।

राजनांदगांव, धमतरी कबीरधाम जिले में धान बीज किल्लत, रायपुर-दुर्ग में उपलब्ध

मांग अधिक होने से महामाया की आपूर्ति में लेटलतफी, किसानों की बड़ी चिंता

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ के किसानों को महामाया धान बीज की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों और बीज केंद्रों में मांग के अनुरूप बीज उपलब्ध नहीं होने से किसानों में चिंता बढ़ गई है। समय पर बीज नहीं मिलने से धान की बोनी और रोपाई प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने कृषि विभाग से महामाया बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। बताया जाता है कि राजनांदगांव, धमतरी, कबीरधाम और अन्य धान उत्पादक जिलों में किसानों द्वारा महामाया धान बीज की उपलब्धता



को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। हालांकि रायपुर और दुर्ग जिले में कृषि विभाग की पर्याप्त बीज उपलब्ध होने का दावा किया है, लेकिन किसानों का कहना है कि लोकप्रिय किस्मों की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है। समिति प्रबंधकों ने बताया कि एक

सप्ताह पहले आपूर्ति नहीं होने के कारण महामाया बीज उपलब्ध नहीं थे। शुक्रवार को इसकी आपूर्ति होने से यह बीज समितियों में मिल रहा है। मांग के मुकाबले कम आवंटन और किसानों द्वारा महामाया किस्म की अधिक मांग-विरण और आपूर्ति में देरी हो रही है।

मध्यम अवधि वाली किस्मों की मांग

सिंचित क्षेत्रों में मध्यम अवधि वाली किस्में तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल्दी पकने वाली किस्मों का वितरण किया जाता है। समितियों के प्रबंधकों का कहना है कि हाल के वर्षों में किसानों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली किस्मों में महामाया, राजेश्वरी और समुद्रीयू-1010 शामिल हैं। इसके चलते कुछ समितियों में इनकी अस्थायी कमी की शिकायतें भी सामने आती हैं। राज्य सरकार और बीज विभाग हर खरीफ सीजन में लाखों विंटल प्रमाणित बीज सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध करते हैं। प्रदेश में 4.87 लाख विंटल बीज का भंडारण

खरीफ 2026 के लिए किसानों की मांग के अनुरूप लगभग 4.95 लाख विंटल प्रमाणित बीज की मांग दर्ज की गई थी, जिसके विरुद्ध लगभग 4.87 लाख विंटल बीज का भंडारण किया गया। इसमें में धान के बीज के लिए 168626 विंटल का भंडारण किया गया है। इनमें से 18752 विंटल बीज वितरित किए जा चुके हैं। समितियों में 149513 विंटल शेष है।

लगभग 1400 से 1500 वर्ष पुरानी मानी जा रही ये ताम्र-पट्टिकाएं पांडुरंगी शाननकाल, विशेषकर मंडई बालार्जुन के कालखंड से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। प्राचीन बाह्मि लिपि और पाली भाषा में अंकित ये अभिलेख तत्कालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक जीवन, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह खोज छत्तीसगढ़ की गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा का संवर्धन प्रमाण है।

चिंतन सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े सुविधाओं का दायरा

भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में फेंसिंग का कार्य शुरू होना केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि वहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन में स्थिरता और विश्वास लौटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। लंबे समय से सीमा के कई हिस्सों में बाड़ नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को घुसपैठ, तस्करी, फसल चोरी और सुरक्षा संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब जब सीमा पर कंट्रोल तार लगाने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो लोगों में नई उम्मीद जगी है। चुनाव के कारण क्षेत्र में ठप पड़े कार्मां पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। भाजपा की नई सरकार बंगाल में विकास के वादे के साथ आई। लोगों को उम्मीद है कि अब यहां सुरक्षा के साथ सुविधाएं भी मिलेंगी। मुर्शिदाबाद जिले के जलंगी बाजार स्थित सकारपाड़ा गांव की स्थिति इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती है। लगभग चार हजार आबादी वाले इस गांव के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। यहां घरों के बाद सीधे खेत खुले जाते हैं और खेतों के बाद बांग्लादेश की सीमा आ जाती है। वर्षों से स्थानीय किसानों की शिकायत रही है कि सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण उनकी फसलें नुकसान का शिकार होती रही हैं। बंगाल की बांग्लादेश के साथ करीब 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबी सीमा मानी जाती है। इसके बावजूद करीब 600 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है, जहां अब तक फेंसिंग का कार्य अधूरा रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत-बांग्लादेश सीमा के अधिकांश हिस्से में बाड़ लग चुकी है, लेकिन शेष क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सीमावर्ती जिलों में फेंसिंग का विस्तार समय की मांग है। हाल के दिनों में नई राज्य सरकार द्वारा बीएसएफ को भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई है। जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, सिलिगुड़ी, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जमीन हस्तांतरण और सुरक्षा ढांचे के विकास का कार्य शुरू हुआ है। यह कदम सीमा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा। बीएसएफ आउटपोस्ट, निगरानी तंत्र और फेंसिंग के माध्यम से अवैध घुसपैठ तथा तस्करी पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। हालांकि केवल बाड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों की सबसे बड़ी समस्या विकास और सुविधाओं का अभाव भी है। इन इलाकों में सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सिंचाई और रोजगार के अवसर अपेक्षाकृत कम हैं। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ इन क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। यदि सीमावर्ती गांवों के युवाओं को रोजगार, किसानों को बेहतर बाजार और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, तभी सुरक्षा उपायों का वास्तविक लाभ समाज तक पहुंचेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी देश की सुरक्षा व्यवस्था का पहला मानवीय चेहरा होते हैं। इसलिए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना राष्ट्रीय हित का विषय है। फेंसिंग से जहां सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीणों की खेती, आवागमन और दैनिक जीवन प्रभावित न हो। इससे घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मजबूत होगा तथा स्थानीय लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, लेकिन इस प्रक्रिया की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब सीमावर्ती गांवों में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा के साथ-साथ विकास, सुविधाएं और बेहतर जीवन के अवसर भी प्राप्त होंगे।

कमजोर मानसून डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा



महंगाई का लगेगा तड़का अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

मौसम विभाग द्वारा जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंता का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोरी मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो-चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी ओर अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात और भी गंभीर होने की आशंका बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर-पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। मानसूनी भी तय समय से विलंबित हो रहा है। एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को मानें तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी, उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है, अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसपास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक सकती है तो निश्चित रूप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता। दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हालांकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है, उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की किस्में विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरूरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कुलों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। इसी तरह से वाटर हार्नेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है, वह किसी से छिपी नहीं हैं। बेमौसम आंधी ओलावृष्टि आम होती जा रही है। कुल मिलाकर, कहीं ना कहीं मानसून को लेकर दीर्घकालीन रणनीति बनानी ही होगी ताकि कमजोर मानसून का जनजीवन और अर्थ व्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़े। सरकारी और गैरसरकारी स्तर पर इस दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।

(लेखक स्वतंत्र संस्कार है, ये उनके अपने विचार हैं।)



शिक्षा नीति अखिलेश आर्येन्दु

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 में कक्षा 9 से त्रिभाषा सूत्र लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद इससे बच्चों में भाषाई, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की मांग भी दशकों से होती रही है। वहीं, दक्षिण में (तमिलनाडु) में हिंदी के विरोध से चुनाव जीते जाते रहे हैं। कुछ खास दलों द्वारा किया गया हिंदी का विरोध शिक्षण संस्थानों और राज्य के मान-सम्मान से भी जोड़ने का कार्य किया गया। त्रिभाषा सूत्र शिक्षण संस्थानों में लागू करने की पहल छह दशक पूर्व की गई थी, लेकिन छात्रों में अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव नहीं पैदा हुआ। इसकी वजह भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देना रहा है। केंद्र सरकार ने इस कमी को समझा और एनसीईआरटी ने सत्र 2026–27 में 9वीं कक्षा में त्रिभाषा फार्मुला लागू करने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है त्रिभाषा सूत्र का फार्मुला कोठारी आयोग ने छह दशक पूर्व दिया था, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिभाषा सूत्र (फार्मुला) कहा जाता है। वक्त-दर-वक्त इसमें संशोधन किए जाते रहे। 2020 के नई शिक्षा नीति के तहत इसे लागू करने का प्रस्ताव किया गया। इसका मकसद बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा देने के रूप में बताया गया। नई शिक्षा नीति के इस भाषाई फार्मुले के दस्तावेज में कहा गया कि –संवैधानिक प्रथाओं, जनता, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए-त्रिभाषा फार्मुला लागू रहेगा। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि त्रिभाषा फार्मुला अधिक लचीला होगा और किसी भी राज्य में कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। देश के हर बच्चे को यह सहूलियत होगी कि वह अपने राज्य, क्षेत्र और रुचि के मुताबिक कोई भी दो भाषा पढ़े, जो भारतीय हों।

नई शिक्षा नीति के अनुसार (एनईपी 2020) छात्र भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा कोरियाई, स्पेनिश, जापानी, जर्मन और फ्रेंच जैसी कोई भी भाषा रुचि के अनुसार सीख सकेगा। नई पीढ़ी में भाषाई

त्रिभाषा से होगा राष्ट्र चेतना का जागरण

द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 में कक्षा 9 से त्रिभाषा सूत्र लागू करने का फैसला किया है। इसका मकसद इससे बच्चों में भाषाई, राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास करना है। गौरतलब है भारत में भाषा का मुद्दा आजादी के बाद से ही चर्चा का विषय रहा है। खासकर हिंदी एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में लागू करने और उसे सम्मान के साथ सीखने का मुद्दा राजनीति के गलियारों में समर्थन व विरोध के रूप में जाना गया है। उत्तर भारत में हिंदी और उसकी बोलियों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने की मांग भी दशकों से होती रही है। वहीं, दक्षिण में (तमिलनाडु) में हिंदी के विरोध से चुनाव जीते जाते रहे हैं। कुछ खास दलों द्वारा किया गया हिंदी का विरोध शिक्षण संस्थानों और राज्य के मान-सम्मान से भी जोड़ने का कार्य किया गया।

त्रिभाषा सूत्र शिक्षण संस्थानों में लागू करने की पहल छह दशक पूर्व की गई थी, लेकिन छात्रों में अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव नहीं पैदा हुआ। इसकी वजह भारतीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देना रहा है। केंद्र सरकार ने इस कमी को समझा और एनसीईआरटी ने सत्र 2026–27 में 9वीं कक्षा में त्रिभाषा फार्मुला लागू करने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है त्रिभाषा सूत्र का फार्मुला कोठारी आयोग ने छह दशक पूर्व दिया था, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इसे त्रिभाषा सूत्र (फार्मुला) कहा जाता है। वक्त-दर-वक्त इसमें संशोधन किए जाते रहे। 2020 के नई शिक्षा नीति के तहत इसे लागू करने का प्रस्ताव किया गया। इसका मकसद बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ भाषाई, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ावा देने के रूप में बताया गया। नई शिक्षा नीति के इस भाषाई फार्मुले के दस्तावेज में कहा गया कि –संवैधानिक प्रथाओं, जनता, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए-त्रिभाषा फार्मुला लागू रहेगा। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि त्रिभाषा फार्मुला अधिक लचीला होगा और किसी भी राज्य में कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। देश के हर बच्चे को यह सहूलियत होगी कि वह अपने राज्य, क्षेत्र और रुचि के मुताबिक कोई भी दो भाषा पढ़े, जो भारतीय हों।

नई शिक्षा नीति के अनुसार (एनईपी 2020) छात्र भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अलावा कोरियाई, स्पेनिश, जापानी, जर्मन और फ्रेंच जैसी कोई भी भाषा रुचि के अनुसार सीख सकेगा। नई पीढ़ी में भाषाई

अभिरुचि के विकास के साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के जागरण के प्रयास में एनसीईआरटी लगा हुआ है। दो भारतीय भाषा सीखने से छात्र जहां भारतीय सांस्कृतिक विविधता और भाषाओं की अहमियत को समझ सकेगा वहीं पर भारत की ज्ञान परंपरा और लोक धर्म को भी समझ सकेगा। गौर तलब है भाषा महज शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम या विषय ही नहीं है, बल्कि उस भाषा में सृजित साहित्य, ज्ञान, परंपराओं के साथ उसमें चिंतन की प्रवृत्ति भी विकसित होगी। आजादी के सतहतर साल बाद भारत के राजनीतिक दलों में भाषा के मुद्दे पर एक समान चिंतन या समझ पैदा नहीं हो पाई है।



इसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि देश में राष्ट्र भाषा या राष्ट्रीय भाषा की अहमियत और समझ विकसित नहीं हो पाई है। जो लोग 2020 की शिक्षा नीति और 9वीं में लागू होने वाली त्रिभाषा शिक्षा नीति को अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध न केवल छात्र के मानसिक और सामाजिक चेतना के विकास में अवरोधक है, बल्कि राष्ट्रीय भाषाई एकता को सबल बनाने की कोशिश पर प्रतिघात जैसा है। भारत आर्थिक रूप से भले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की दिशा में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन राष्ट्र एकता की आधार भाषाई एकता के मामले में सबसे पीछे है।

गौरतलब है कि एनसीईआईआरटी ने हर क्षेत्र और हर तरह के छात्रों-छात्राओं के हित को ध्यान में रखकर इसे लागू किया है। विदेशी छात्रों, दिव्यांग छात्रों और दूसरे तरह के छात्रों को इस फार्मुला से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी शैक्षिक सहजता, मानसिक संतुलन और व्यावहारिक जरूरतों को इससे पूर्ति हो पाएगी। बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र के हर बिंदु और नजरिए पर शिद्दत के साथ गौर किया है। आजादी के वक्त और उसके बाद राष्ट्र भाषा का मुद्दा हल नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत की कोई राष्ट्र भाषा संविधान में ईंगित नहीं हो

हर युग में प्रासंगिक ‘महादेव’

कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आदियोगी शिव का प्रशंसक हूं। प्रशंसक होने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से जुड़ जाना। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं शिव को महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं, क्योंकि उनका योगदान काल के परे है। इसलिए वे सदा प्रासंगिक हैं। किसी भी पीढ़ी में किसी इंसान की प्रशस्ति उस योगदान के लिए की जाती है, जो उसने उस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ियों के लिए किया है। इस धरती पर कई ऐसे लोग आए हैं, जिन्होंने दूसरों के जीवन में योगदान किया है। जो उस समय की जरूरत के अनुसार था, वह उसे लेकर आया। गौतम बुद्ध के समय समाज कर्मकांडों में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने बिना किसी कर्मकांड के आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू की तो वह लोकप्रिय हो गए। अगर समाज में कर्मकांड नहीं होते, तो वह इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन फिर भी, यदि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध नहीं होता, तो वह सिर्फ अपने आसपास की जगहों पर प्रभावशाली होते। आदियोगी या शिव का महत्व यही है कि उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ। उन्होंने मानव चेतना को इस प्रकार से विकसित करने के साधन और तरीके दिए कि वे हर युग में प्रासंगिक रहें। हमने उन्हें महादेव की उपाधि दी, क्योंकि उनके योगदान के पीछे की बुद्धि, दृष्टि और ज्ञान अद्भुत है।

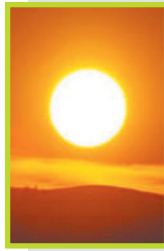
अंतर्मन



करंट अफेयर

बच्चे नए तंबाकू उत्पादों के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं

वयस्कों की तुलना में बच्चों के नये तंबाकू और निकोटीन उत्पादों की ओर आकर्षित होने की आशंका भी गुना अधिक होती है, जिससे वे इस उद्योग की विपणन रणनीतियों का प्रमुख शिकारबन रहे हैं। यह बात प्रमुख जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रविवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर चेतावनी देते हुए कही। विशेषज्ञों ने कहा कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग अपने उत्पादों को युवाओं के लिए आकर्षक बनाने के रास्ते स्वादयुक्त विकरणों, आकर्षक डिजाइन, डिजिटल प्रचार और अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे नई पीढ़ी के निकोटीन की लत से ग्रस्त होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दुनिया इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस ‘अनमारस्किंग द अपील: काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन’ विषय के साथ मना रही है। इसका उद्देश्य तंबाकू और निकोटीन उत्पादों को विशेष रूप से बच्चों के लिए आकर्षक दिखाने हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों और तौर-तरीकों को उजागर करना है। भारतीय आर्युर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) निदेशक शालिनी सिंह ने कहा कि तंबाकू और निकोटीन उद्योग अवसर बच्चों और युवाओं को अपने विपणन प्रयास में केंद्रित करता है।



शामिल था। यही तकनीक चिकित्सा लेखन में भी है जिसका श्रेय यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस को दिया जाता है जिनका काल लगभग 450–380 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 150 ई. में आधुनिक तुर्की में सक्रिय रहे चिकित्सक एरेटियस ने लिखा था कि सूर्य का प्रकाश सूरती सहित कई बीमारियों को ठीक कर सकता था। इसमें वह बीमारी भी है जिसे हम आज अवसाद के रूप में पहचानते हैं। सुस्ती मिलाने का अर्थ है प्रकाश में लेटना, सूर्य की किरणों के संपर्क में आना; तथा अपेक्षाकृत गर्म स्थान में रहना।

संकलित प्रेरणा



संकलित प्रेरणा

गुरु का स्थान श्रेष्ठ

एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्री-परिषद् के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महिने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता थे परन्तु राजा को उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान, गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दी कि राजन आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखिए। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरुजी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, हे गुरुवर क्षमा कीजिएगा, मैं कई महिनो से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया- राजन इसका कारण बहुत ही सीधा सा है.. गुरुवर कृपा कर के आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा- राजन बात बहुत छोटी है परन्तु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं। आप हर दृष्टि से मुझ से पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं परन्तु यहां पर आप का और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है।. गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे उच्च होना चाहिए, परन्तु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बैठाते हैं।

टेंडें

गंगा डॉलिफन की रक्षा

गंगा डॉलिफन की रक्षा करके हम न केवल एक प्रजाति का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की अमूल्य विरासत की रक्षा भी कर रहे हैं। इस दिशा में देश की पहली डॉलिफन बचाव एग्युलेशन बेहद उपयोगी साबित हो रही है।
- नरेंद्र मोदी, मोदी

सांसद पर हमला निंदनीय

सोनाएपुर में सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। यह भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति का सिंनोना चेहरा है। राजनीतिक मतभेद कभी भी हिंसा को उचित नहीं ठहरा सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार, दोनों को ही अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

जवाबदेही तय की जाएगी

सभी अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर स्तर पर लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। कोई भी बिल्डर, अधिकारी या प्राधिकरण काजून से ऊपर नहीं है। दिल्ली सरकार अपने लोगों के साथ खड़ी है।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

क्षष्ट भाजपा राजनीति

भाजपा बेईजानी से चुनाव जीती है, इस तथ्य को भाजपा के एक विधायक ने स्वीकार किया है, जिन्होंने एक वृत्तरोड़ में क्षष्ट भाजपा राजनीति का पर्दाफास किया है और उसे कुपुल भी दिया है। इस बात जगता भाजपा के सारे हथकंडे उजागर कर देगी।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

रिंग रोड नं . 2 , गौरवपुर, बिलासपुर
फोन : 401050,271016,फैक्स-271018
ई-मेल : haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

मशीनी जंग : यूक्रेन के ‘साइलेंट डेथ’ रोबोट के खौफ में रूसी सैनिक, दुनिया हैरान

एजेंसी ►► कौबू

रूस और यूक्रेन के बीच चार सालों से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध का मैदान नाटकीय रूप से बदल रहा है। फरवरी 2022 में टैंक, तोपखाने और पैदल सेना के साथ शुरू हुआ यह सैन्य संघर्ष पर अब मशीनों का युद्ध बनता जा रहा है। अब रोबोट, ड्रोन और रिमोट से चलने वाले वाहन उन मिशनों को अंजाम दे रहे हैं, जिनके लिए हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। रूसी सैनिकों ने इन रोबोट को साइलेंट डेथ नाम दिया है, क्योंकि अक्सर धमाका होने के ठीक पहले ही इनकी आवाज सुनाई देती है।

यूक्रेन की मशीनी सेना कर रही रूस का मुकाबला

इस युद्ध में सैनिकों की कमी से जुड़ा रहे यूक्रेन ने एक जबरदस्त बदलाव किया है। उसके युद्ध अभियानों का एक बड़ा हिस्सा अब मानवरहित हो गया है। सैनिकों की जगह यूक्रेनी सेना रोबोट, ड्रोन और दूर से कंट्रोल किए जाने वाले टैंकों से रूस का मुकाबला कर रही है, जिसने उसे अचानक बढ़त दिला दी है। युद्ध के सबसे खतरनाक अग्रिम मोर्चों पर तकनीक तेजी से सैनिकों की जगह ले रही है।

जंग में रोबोट का हो रहा इस्तेमाल

यूक्रेनी सैन्य इकाइयां अब बारूद ले जाने वाले जमीनी रोबोट का इस्तेमाल करके हमले कर रही हैं। इन्हें युद्ध के मैदान से कई किलोमीटर दूर बैठे ऑपरेटर नियंत्रित करते हैं। अब ये मशीनी सेना इतनी ताकतवर हो चुकी है कि रूसी ठिकानों पर कब्जा कर रही है। इसी अप्रैल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि पहली बार किसी रूसी ठिकाने पर रोबोट और ड्रोन की मदद से कब्जा किया गया।



रूसी सैनिकों ने दिया साइलेंट डेथ नाम

जेलेंस्की ने यह भी बताया कि जनवरी से अप्रैल के बीच यूक्रेन की मानवरहित मशीनों ने 22000 मिशन पूरे किए हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ये मशीनें धमाका करने से पहले खाइयों और पेड़ों की कतारों से होकर दुश्मन के पास पहुंचती हैं। रूसी सैनिकों ने इन रोबोट को साइलेंट डेथ नाम दिया है, क्योंकि अक्सर धमाका होने के ठीक पहले ही इनकी आवाज सुनाई देती है।

यूक्रेन का लक्ष्य प्रति माह 35,000 रूसियों को मारना है

यूक्रेनी अधिकारियों का लक्ष्य अब हर महीने लगभग 35,000 रूसी सैनिकों को हताहत करना है, और उनका कहना है कि इस साल यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस रणनीति का उद्देश्य क्रेमलिन पर दबाव बढ़ाना है, ताकि वह रूस की शहरी आबादी और मध्यम वर्ग से अधिक संख्या में सैनिकों की भर्ती करने के लिए मजबूर हो जाए। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी जीसीएचक्यू द्वारा बुधवार को जारी एक नए अनुमान के अनुसार, रूस में कुल सैन्य मृतकों की संख्या लगभग 500,000 है।

खबर संक्षेप

थुमेंट्रु मंत्रिमंडल का विस्तार आज, 35 मंत्री लेंगे शपथ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने



रविवार को घोषणा की कि उनके मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत सोमवार को 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल आरएन. रवि सुबह 11 बजे लोक भवन में शपथ दिलाएंगे। उन्होंने रविवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “कल पश्चिम बंगाल की जनता द्वारा चुनी गई राष्ट्रवादी सरकार के पूर्ण मंत्रिपरिषद का गठन होगा।”

पीओके में घुसने की कोशिश कर रहे तीन पकड़ाए

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना ने तीन लोगों को



पकड़ लिया और कथित तौर पर देश से बाहर निकलने के उनके प्रयास को विफल कर दिया, जबकि एक अलग घटना में जवानों ने नियंत्रण रेखा पार करने के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसने के आरोप में गिरफ्त में ले लिया। श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कहा कि उरी क्षेत्र में सोपोर के दो व्यक्तियों को सतर्क चिनार योद्धाओं ने उरी सेक्टर में अपने सहयोगी गाइड के साथ शत्रुतापूर्ण इरादे से भागने का प्रयास करते समय पकड़ लिया।

केंद्रीय मंत्री रवनीत ने दलित समुदाय से मांगी माफी

चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी हालिया



आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए रविवार को अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय से माफी मांगते हुए कहा कि एक मंत्री के रूप में उन्हें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। भाजपा के नेता बिट्टू ने कहा कि वह पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बिट्टू की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब आयोग ने संगठन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बिट्टू द्वारा कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणियों के इस्तेमाल के संबंध में एक जून तक रिपोर्ट मांगी है।

एजेंसी ►► नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि टेक्स खेल के नतीजे या कसीनो के अंतिम मुनाफे पर नहीं, बल्कि खिलाड़ी द्वारा दांव लगाते ही लागू हो जाएगा। कोर्ट ने कसीनो कंपनियों को उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें टैक्स सिर्फ ‘ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू’ पर लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कसीनो और जुआ गतिविधियों में जीएसटी की गणना खिलाड़ियों के दांव लगाने के समय से होगी, न कि खेल खत्म होने के बाद कसीनो के वास्तविक मुनाफे के आधार पर।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

कसीनो कंपनियों की दलीलों की खारिज

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कसीनो कंपनियों की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जीएसटी केवल ग्रांश गेमिंग रेवेन्यू (जीजीआर) यानी खिलाड़ियों को जीत की राशि देने के बाद बची रकम पर ही लगाया जाना चाहिए। कसीनो का तर्क था कि यदि जीएसटी लागू हो जाता है। इसके लिए खेल का नतीजा आने या खिलाड़ी के जीतने-हारने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

जीएसटी कर योग्य आपूर्ति पर लगाया जाता है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीएसटी किसी कारोबारी के लाभ या हानि पर नहीं, बल्कि कर योग्य आपूर्ति (टेक्सेबल सप्लाई) होने पर लगाया जाता है। अदालत ने कहा कि जैसे ही कोई व्यक्ति कसीनो में चिप्स या टोकन खरीदकर किसी खेल में दांव लगाता है, उसी समय जीएसटी लागू हो जाता है। इसके लिए खेल का नतीजा आने या खिलाड़ी के जीतने-हारने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।



चिप्स व टोकन के जरिए लेनदेन : अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कसीनो में इस्तेमाल होने वाले चिप्स और टोकन केवल दांव लगाने का माध्यम हैं। खिलाड़ी इनके बिना खेल में भाग नहीं ले सकता। इसलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चिप्स या टोकन के जरिये होने वाले लेनदेन में कोई कर योग्य दावा उत्पन्न नहीं होता। पीठ ने कहा कि यदि जीएसटी की गणना केवल कसीनो के अंतिम लाभ या हानि के आधार पर की जाए तो इससे कर देयता को कम दिखाने या छिपाने की संभावना पैदा हो सकती है। इसके विपरीत, खिलाड़ी की ओर से दांव लगाए जाने के आधार पर कर निर्धारित करने से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी रहती है।

अदालत ने जीत-हार पर की बड़ी टिप्पणी

अदालत ने कहा कि जब कोई खिलाड़ी दांव हार जाता है, तो कसीनो उस रकम को अपनी कमाई मानता है लेकिन जब कोई खिलाड़ी बड़ी रकम जीत जाता है, तो कसीनो यह कहता है कि उसे नुकसान हुआ है, इसलिए उस राशि पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स, कसीनो और दांव आधारित अन्य खेलों में जीएसटी की देनदारी खिलाड़ी की ओर से दांव लगाए जाने के समय ही तय होगी और इसे कसीनो के अंतिम वित्तीय परिणाम से नहीं जोड़ा जा सकता।

‘मन की बात’ में पीएम का खास संदेश

एजेंसी ►► नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड में देशवासियों से कई अहम बातें शेयर कीं। उन्होंने युवाओं की अद्भुत प्रतिभा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के एथलीट नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय एथलीट गुरिंदरवीर सिंह और अनिमेष कुजूर से बातचीत का जिक्र भी किया। गुरिंदरवीर ने बताया, ‘मैं इंडियन नेवी में पेटी ऑफिसर हूं और भारत का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। हाल ही में मैंने 100 मीटर में 10.09 सेकंड का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वहीं, अनिमेष कुजूर ने बताया कि वो भी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में बताया कि हाल ही में उन्हें नींदरलैंड्स जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया।

युवा बना रहे रिकॉर्ड, एस्ट्रोनॉमी पर भारतीयों का आकर्षण ज्यादा

चोल काल की धरोहर भारत को मिलीं



ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

खगोल विज्ञान पर भारतीयों का आकर्षण

पीएम मोदी ने खगोल विज्ञान का जिक्र करते हुए कहा, भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की प्रति हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। आजकल देशभर में एस्ट्रोनॉमी क्लब तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं।

भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की एक घटना है, जहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में ‘नमामि गंगे अभियान’ के तहत बनी एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस...



कोलकाता। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर देशभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं और खासकर विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपने आकर्षक पोस्टरों और प्रभावशाली विचारों के माध्यम से तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों को दर्शाया तथा लोगों को इसके प्रति जागरूक होने का संदेश दिया।

आतंकियों के नए हथियार का तोड़ निकालने में जुटी एजेंसियां

एजेंसी ►► जम्मू

भारतीय अधिकारी पाक अधिकृत कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में पहुंच रहे टेलीकॉम सिग्नल्स की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। सीमा पर नए टावर लगाए जाने से ये सिग्नल आतंकवादी गुटों को आपस में संपर्क बनाए रखने का जरिया बन रहे हैं और साथ ही भारतीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को धोखा देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तकनीक की इस नई चाल ने स्थानीय अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं।



भारतीय एजेंसियां सिग्नल्स रोकने के लिए कर रही काम

ये गैरकानूनी सिग्नल सिर्फ सरहद पार ही नहीं करते, बल्कि जम्मू-कश्मीर की जेलों में बंद उजवाड़ियों को भी अपने साथियों से बातचीत करने या भागने की योजना बनाने का मौका दे सकते हैं। इस खतरे से निपटने के लिए भारतीय एजेंसियां इन ट्रान्समिशनों को रोकने या निष्क्रिय करने के लिए तकनीकी उपाय ढूंढ रही हैं। सरकार इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है और इन सिग्नल्स को रोकने के लिए एजेंसियां लगातार तकनीकी हल खोजने में जुटी हैं।



काँफी डे ग्लोबल ने कमाया 14 करोड़ का शुद्ध लाभ

नई दिल्ली। कैफ़े काँफी डे का संचालन करने वाली कंपनी काँफी डे ग्लोबल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि उसकी परिचालन 5.7 प्रतिशत बढ़कर 1,094 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी की मूल इकाई काँफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का परिचालन लाभ या कर-पूर्व-आय (ईबीआईटीडीए) 27 प्रतिशत बढ़कर 198 करोड़ रुपये हो गया।

असम के चिप संयंत्र में इसी वर्ष से उत्पादन

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि असम के जगोरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र में इसी वित्त वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। वैष्णव ने शनिवार शाम असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से हुई मुलाकात के बाद यह बात कही। वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, 'असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उनसे जगोरोड स्थित सेमीकंडक्टर संयंत्र की प्रगति पर चर्चा की गई। हमारा लक्ष्य इस वित्त वर्ष के भीतर इस संयंत्र से उत्पादन शुरू करना है।'

उद्योग को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि

मुंबई। उद्योग क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण की वृद्धि दर अप्रैल 2026 के अंत में बढ़कर 15.1 प्रतिशत रही। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में सात प्रतिशत थी। आरबीआई ने 41 चर्चनित बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बताया कि ये बैंक कुल गैर-खाद्य बैंक ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 को समाप्त पखवाड़े में गैर-खाद्य बैंक ऋण में सालाना आधार पर 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि 9.8 प्रतिशत थी।

सेबी के जर्माना आदेश को सैट में चुनौती देगी सुजलॉन

नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने कहा कि वह कंपनी, उसके दो प्रवर्तकों और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारियों (सीएफओ) पर 28.95 करोड़ रुपये का जर्माना लगाने वाले सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करेगी। बीएसई को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने 29 मई, 2026 को एक आदेश पारित किया, जिसमें उसने 27 जून, 2025 को दिए गए एक पूर्व न्यायिक निर्णय को रद्द कर दिया।

बीते सप्ताह सरसों तेल में रहा सुधार

नई दिल्ली। कम आवक के बीच अचार के मौसम की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह तेल-तिलहन बाजारों में सरसों तेल के दाम में मामूली सुधार देखा गया। कम उपलब्धता के बीच मांग बढ़ने से बिनोलातेल के दाम में भी सुधार आया। दूसरी ओर, डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोयाबीन तेल-तिलहन तथा पाम-पामोलीन तेल के दाम गिरावट दर्शाते बंद हुए। गर्मी की फसल की आवक शुरू होने की चर्चा के बीच मृगफली तेल-तिलहन के दाम स्थिर रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक कमजोर बनी हुई है।

बीते सप्ताह सरसों तेल में रहा सुधार

नई दिल्ली। कम आवक के बीच अचार के मौसम की मांग बढ़ने से बीते सप्ताह तेल-तिलहन बाजारों में सरसों तेल के दाम में मामूली सुधार देखा गया। कम उपलब्धता के बीच मांग बढ़ने से बिनोलातेल के दाम में भी सुधार आया। दूसरी ओर, डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोयाबीन तेल-तिलहन तथा पाम-पामोलीन तेल के दाम गिरावट दर्शाते बंद हुए। गर्मी की फसल की आवक शुरू होने की चर्चा के बीच मृगफली तेल-तिलहन के दाम स्थिर रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक कमजोर बनी हुई है।

डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाना हो सकता है साल अंत तक अनिवार्य

एजेंसी ►► नई दिल्ली

देश में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और परिवहन क्षेत्र को कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करने के लिए सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण अनिवार्य करने का प्रस्ताव इस वर्ष के अंत तक ला सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'डीजल में मिश्रण (ब्लेंडिंग) को गंभीरता से देखा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम इस दिशा में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण पर शोध कर रही है, जिसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक

सरकार अनिवार्य करने का प्रस्ताव वर्ष अंत तक ला सकती है

पेट्रोल से डीजल की खपत दोगुना

सचिव ने कहा कि डीजल की खपत पेट्रोल से लगभग दोगुनी होने की वजह से इस ईंधन में मिश्रण का प्रभाव देश की ऊर्जा सुरक्षा पर और भी अधिक होगा। उमाशंकर ने कहा, 'इस वर्ष के अंत तक डीजल में मिश्रण को अनिवार्य करने का प्रावधान लागू किए जाने की संभावना है। परिवहन सचिव ने कहा कि मंत्रालय पिछले 10-12 वर्षों में आगे बढ़ने वाले ईंधन मिश्रण कार्यक्रम को और आगे बढ़ा रहा है।



पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा

इस क्रम में ई85 पेट्रोल (85 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल) और ई100 (लगभग शुद्ध एथेनॉल आधारित ईंधन) से जुड़े वाहन विनिर्माण नियमों का मसौदा भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत पहले ही पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जिससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और उत्सर्जन घटाने में मदद मिली है।

कंपनी के सीईओ दुर्इस्वामी ने कहा बढ़ती डिजिटल जरूरतें पूरी की जाएगी

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उतरने की तैयारी में एलआईसी, रणनीतिक निवेश की भी योजना : सीईओ

एजेंसी ►► नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है। कंपनी रणनीतिक निवेश के जरिये या स्वयं नई इकाई स्थापित कर फिनटेक कारोबार शुरू करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अ धि का री (सीईओ) और प्रबंध निदेशक आर दुर्इस्वामी ने यह बात कही है। दुर्इस्वामी ने कहा कि बदलते दौर की जरूरतों और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा बीमा प्रौद्योगिकी (इंश्योरेटेक) कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही, एलआईसी विभिन्न



सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित

सीईओ ने बताया कि एलआईसी प्रौद्योगिकी नवाचार अपनाने वाली शुरुआती इकाइयों में रही है। कंपनी ने अपने व्यावसायिक अनुप्रयोग विकसित करने के लिए सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित किया है, जहां बड़ी संख्या में विशेषज्ञ कार्यरत हैं। हालांकि, आधुनिक प्रौद्योगिकी दृष्टि और नए डिजिटल मॉडों के विकास के लिए बाहरी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं का सहयोग भी लिया जाता है।

कंपनी अपनी आईटी प्रणालियों का आधुनिकीकरण कर रही

दुर्इस्वामी के अनुसार, एलआईसी अपने आंतरिक प्रौद्योगिकी दल और बाहरी प्रौद्योगिकी साझेदारों, दोनों की क्षमताओं का उपयोग कर रही है। कंपनी विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है और भविष्य में किसी रणनीतिक साझेदारी या नई पहल की घोषणा कर सकती है। उनका कहना है कि एलआईसी का मुख्य उद्देश्य अपनी आईटी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना और प्रतिस्पर्धा के बीच अधिक चुस्त एवं प्रभावी बनना है।

संस्थानों में निवेश करने वाली बड़ी उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की वित्तीय इकाई होने के नाते ऐसे विशेष संभावनाएं भी तलाश रही है।

सरकार की और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी

केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में एलआईसी में और हिस्सेदारी बेचने की संभावना पर उन्होंने कहा कि कंपनी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की तैयारी के समय से ही ऐसी संभावित प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया था। उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी बिक्री का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और जब भी ऐसा होगा, एलआईसी उसके सफल क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करेगी।

सरकार ने कंपनी में 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में एलआईसी का आईपीओ आया था, जिसके माध्यम से सरकार ने लगभग 21,000 करोड़ रुपये जुटाए थे और कंपनी ने अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इससे पहले एलआईसी पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व में थी। उन्होंने कहा कि सरकार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए निर्धारित न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी मानकों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए उचित समय का इंतजार किया जा रहा है।

पहली बार लामांश की सिफारिश

दुर्इस्वामी ने कहा कि आईपीओ के बाद एलआईसी ने शेयरधारकों को बेहतर प्रतिक्रिया देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। हाल ही में कंपनी ने एक के बदले एक बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की और लामांश में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये के अंतिम लामांश की सिफारिश की है।

सेंट्रल बैंक की संपत्ति प्रबंधन व क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू करने की योजना

एजेंसी ►► नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में संपत्ति प्रबंधन सेवाएं और क्रेडिट कार्ड कारोबार शुरू करने की योजना बनाई है।

■ चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से शुरू करने की योजना बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अ धि का री (सी ई ओ) ने कहा है।

कल्याण कुमार ने कहा कि इसके लिए निदेशक मंडल से मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा, 'हम इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले साझेदारों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि यह कारोबार शुरू किया जा सके। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के मध्य तक हम इसे शुरू करने की स्थिति में होंगे। कुमार ने कहा कि बैंक गैर-ब्याज आय बढ़ाने वाले अन्य उत्पाद भी पेश करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए



नकदी प्रबंधन सेवाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। यह उत्पाद विकसित किया जा रहा है और अगस्त तक इसे पेश किए जाने की उम्मीद है।

विदेशी मुद्रा कारोबार भी शुरू कर रहे

सीईओ ने कहा, 'हम ऋण पत्र (एलसी) और गारंटी पत्र (एलजी) के कारोबार के जरिये विदेशी मुद्रा लेनदेन को केंद्रीकृत कर रहे हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि शुरुआत में बैंक अपने उन कॉर्पोरेट ग्राहकों को लक्ष्य बनाएगा जो वर्तमान में ये सेवाएं अन्य बैंकों से ले रहे हैं।

बाजार पूंजीकरण में रिलायंस को सबसे ज्यादा नुकसान

एजेंसी ►► नई दिल्ली

नई दिल्ली। बीते सप्ताह स्थानीय शेयर बाजार में आई गिरावट का असर देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों पर भी देखने को मिला। सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण में साप्ताहिक रूप से कुल 1.54 लाख करोड़ रुपये से अधिक की गिरावट आई। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। सप्ताह के दौरान बीएसई का 30 शेयर्स वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स कुल 639.61 अंक यानी 0.84 प्रतिशत और एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी 171.55 अंक यानी 0.72 प्रतिशत नीचे आ गया। बाजार में कमजोरी के इस रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरलैन्स, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), बजाज फार्मस और हिंदुस्तान यूनीलीवर के बाजार मूल्योत्पन्न में गिरावट दर्ज की गई।



संघन नारा
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE

INVITING APPLICATIONS FOR GRANT-IN-AID UNDER THE SCHEME OF "FINANCIAL ASSISTANCE TO CULTURAL ORGANIZATIONS WITH NATIONAL PRESENCE" FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27.

The Ministry of Culture, Government of India invites applications/ proposals from Cultural Organizations under aforementioned scheme with the objective to provide financial assistance to Cultural Organizations having National Presence to meet the expenditure to be incurred on conducting the cultural programmes/festivals, etc. Details of scheme guidelines, eligibility criteria, prescribed application format, details of required documents, etc. are available on the website of Ministry of Culture i.e. <https://culture.gov.in/offering/schemes-services/financial-assistance-cultural-organizations-national-presence>

Eligible applicant organizations should submit two copies of applications, complete in all respect latest by 15th July, 2026 (5.00 PM) at the following address:-

Director, Eastern Zonal Cultural Centre
IB-201, Sector 3, Salt Lake City
Bidhannagar, Kolkata-700106, West Bengal

Incomplete applications and applications received after last date of receipt of applications WILL BE SUMMARILY REJECTED.

Canvassing by the applicant organizations in any form will lead to disqualification of proposal.

एजेंसी ►► नई दिल्ली

शेयर बाजार में अगले सप्ताह दो कंपनियों सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज और हेक्सामान न्यूट्रिशन के कुल लगभग 770 करोड़ रुपये के आ रं भि क सार्वजनिक निर्गम (आई पी ओ) खुलने जा रहे हैं। दोनों ही कंपनी के



आईपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) है, इसलिए कंपनियों को इस सार्वजनिक निर्गम से कोई

42 से 45 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय

कंपनी ने अपने 139 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के लिए 42-45 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। प्रस्तावित आईपीओ में प्रवर्तकों द्वारा 3.08 करोड़ से अधिक शेयर्स का ओएफएस शामिल है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर निर्गम का आकार 138.87 करोड़ रुपये आंका गया है। राशि प्राप्त नहीं होगी।

फाईल सं. 1-9/2025-एसकेटी.। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

दिनांक 25.05.2026

विज्ञापन संख्या-04/2026

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के कुलपति के पद पर नियुक्ति पर विचार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

कुलपति, अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख हैं और विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इस पद पर विचार के लिए पात्रता की शर्तें और अन्यथा निम्नानुसार हैं :

- संस्कृत और संबद्ध विषयों के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान और उसकी अहर्ताएं विश्वविद्यालय अनुदान आयाग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के तहत बनाए गए विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अहर्ताएं होंगी।
- इस विज्ञापन में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 65 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना वांछनीय।

वेतन और सेवा शर्तें:

- पद पर प्रतिमाह वेतन 2,10,000/- रुपये (नियत) और 11,250/- रुपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्ते देय होगा।
- सेवाओं के अन्य नियम और शर्तें, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 और विश्वविद्यालय की संविधियों और अध्यादेश में निर्धारित के अनुसार होंगी।

नियुक्ति की प्रक्रिया:

- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल से नियुक्ति की जाएगी।

आवेदन जमा करना:

- विज्ञापन वेबसाइट <https://www.education.gov.in> और <https://www.slbsrsv.ac.in> पर उपलब्ध है।
- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए लिंक के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के समर्थ पोर्टल पर ‘ ‘केवल ऑनलाइन आवेदन’ ’ करना होगा : <https://vcrc.samarth.ac.in/index.php/>
- मंत्रालय किसी भी कारण से आवेदन प्राप्त होने में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो व्यक्ति पहले से ही सेवारत हैं, उन्हें उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए और अपने संस्थान/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सतर्कता निकासी रिपोर्ट के साथ अपने नियोक्ता के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना चाहिए।
- अपूर्ण आवेदनों/आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा अपूर्णत लिंक 01 जून, 2026 10:00 बजे से दिनांक 30 जून, 17:00 बजे तक सक्रिय रहेगा।

-हस्ता/-
(डॉ. सोम्य राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर: 23070182

[illegible]

1997 में जिस समंदर ने भारत को सूखे से बचाया था, 2026 में वो है खामोश

भारत में मानसून को लेकर इस साल गई चिंता सामने आई है। वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि इस साल भारत के मानसून पर अल नीनो का सबसे खतरनाक असर दिख रहा है। जब भी अल नीनो आता है, भारत के लिए परेशानी का कारण बनता है।

नई दिल्ली। अगर अल नीनो का असर भारत पर पड़ता है, तो सीखे की स्थिति बढ़ सकती है। लेकिन, इस बार स्थिति थोड़ा अलग है। साल 2026 में आने वाले अल नीनो को लेकर ही चिंता नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी टेशन है हिंद महासागर का खामोश बैठना।

आमतौर पर जब भी प्रशांत महासागर में अल नीनो एक्टिव होता है, तो भारत में सूखा पड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन, साल 1997 में इतिहास का सबसे खतरनाक अल नीनो आने के बाद भी भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे अपने हिंद महासागर ने ढाल बनकर मानसून बचाया था। लेकिन, इस बार कहानी पूरी तरह से अलग है। डेटा बता रहा है कि 2026 में हिंद महासागर पूरी तरह शांत बैठा है, जिससे भारत के पास अल नीनो से लड़ने का कोई बैकअप प्लान नहीं बचा है।

अल नीनो के खतरे ने बढ़ाई आईएमडी की टेंशन

क्या है अल नीनो

प्रशांत महासागर में जब भी पूरब से पश्चिम चलने वाली हवाएं कमजोर होती हैं, तो समुद्र का गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तटों की ओर जमा होने लगता है। पानी के इस तरह गर्म होने की घटना को अल नीनो कहते हैं। इसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है। मानसून का नियम है, जब गर्मियों में भारत की जमीन तपती है, तो हिंद महासागर से नमी वाली ठंडी हवाएं खिंची चली आती हैं और बारिश होती है। लेकिन, अल नीनो इस पूरे सिस्टम को खराब करने का काम करता है। अल नीनो बादलों और नमी को भारत से दूर प्रशांत महासागर की ओर खींच लेता है, जिससे भारत में बारिश कम होती है। आंकड़ों के अनुसार 1951 से 2022 के बीच 60% अल नीनो वाले सालों में भारत में सूखा या कम बारिश हुई है।



हिंद महासागर बना था ढाल

जब अल नीनो मानसून को कमजोर करने की कोशिश करता है, तो हिंद महासागर एक्टिव हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। इसमें अफ्रीका के पास का समंदर गर्म हो जाता है और इंडोनेशिया के पास का पानी ठंडा रहता है। यह स्थिति दो प्रकार की होती है। पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी।

पॉजिटिव आईओडी

यह स्थिति भारत के लिए एक वरदान की तरह काम करती है, क्योंकि यह मानसून की हवाओं को दोबुनी ताकत से भारत की ओर धकेलता है। 1997 में इसी पॉजिटिव आईओडी ने अल नीनो के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया था।

किसानों की बढ़ सकती है मुसीबत

सितंबर के महीने में अल नीनो का असर सबसे खतरनाक होगा। यह वही महीना है जब किसानों की फसल धान, दालें, कपास और तिलहन पकने की कगार पर होती है। वैज्ञानिक इसे ग्रेन-फिलिंग स्ट्रेज कहते हैं, जिसमें पौधों के दानों में न्यूट्रिएंट्स मरते हैं। इस समय फसलों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर सितंबर में बारिश रुकी, तो पूरी की पूरी तैयार फसल बाबाद हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए आईएमडी ने मानसून का अनुमान घटकर 90% कर दिया है, जो सामान्य से कम की श्रेणी में आता है। इस साल सूखा पड़ने की आशंका 60% तक बढ़ गई है, जो आम सालों में महज 16% होती है।

रोचक खबरें



भारत में अनोखा पानी में तैरने वाला चर्च, हर 6 महीने में बदलता है रंग

बेंगलुरु। कर्नाटक की हरी-भरी वादियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह मौजूद है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह है शेड्रीहल्ली रोजरी चर्च, जो हर मानसून में पानी के बीच अकेला खड़ा दिखाई देता है। चारों तरफ फैला गहरा पानी, टूटी हुई पुरानी दीवारें और सन्नाटे से भरा माहौल इस जगह को किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म जैसा बना देता है। यही वजह है कि लोग इसे फ्लोटिंग चर्च और कर्नाटक का हॉन्टेड चर्च तक कहने लगे हैं। हालांकि, इस चर्च की असली पहचान इसकी डरावनी कहानियों में नहीं, बल्कि इसके शानदार इतिहास और अनोखी खूबसूरती में छिपी है।

इस चर्च का निर्माण 1860 के दशक में फ्रांसीसी मिशनरियों ने करवाया था। उस समय यह चर्च इलाके में रहने वाले ब्रिटिश एस्टेट मालिकों और स्थानीय ईसाई समुदाय के लिए प्रार्थना का मुख्य केंद्र हुआ करता था। फ्रेंच गोथिक शैली में बने इस चर्च की ऊंची मेहराबें, पत्थरों पर की गई नक्काशी और बड़ी-बड़ी खिड़कियां इसकी भव्यता को अलग पहचान देती थीं। हेमावती नदी के किनारे बना यह चर्च कभी लोगों की प्रार्थनाओं और धार्मिक गतिविधियों से गुलजार रहता था। लेकिन, 1960 के दशक में इसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। हेमावती बांध बनने के बाद आसपास का इलाका धीरे-धीरे जलाशय में बदलने लगा। पानी का स्तर बढ़ने से गांव खाली कराए गए और लोगों को दूसरी जगह बसना पड़ा। इसी के साथ यह चर्च भी वीरान हो गया। समय के साथ इसकी छत गिर गई, दीवारें टूटने लगीं, लेकिन इसके विशाल खंभे और मेहराब आज भी मजबूती से खड़े हैं। मानसून के मौसम में यह चर्च आधा पानी में डूब जाता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी इमारत झील के ऊपर तैर रही हो। वहीं सर्दियों में पानी कम होने पर लोग पैदल यहां तक पहुंच सकते हैं।

यही वजह है कि यह चर्च हर मौसम में अलग रूप दिखाता है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई भूतिया कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। हालांकि, यहां किसी पैरानॉर्मल घटना का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। असल में इसका सुनसान माहौल, पानी के बीच खड़ा पुराना ढांचा और धुंध से घिरा दृश्य लोगों को रहस्यमयी एहसास देता है। आज यह जगह ट्रेवलर्स, फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए खास आकर्षण बन चुकी है।

दुनिया का अनोखा आइलैंड, जहां है सुअरों का राज! समुद्र में टूरिस्ट के साथ लगाते हैं गोते



नासाउ। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपनी अनोखी खासियतों की वजह से लोगों को हैरान कर देती हैं। ऐसी ही एक जगह बहामास के एकमुआ इलाके में मौजूद पिग आइलैंड है, जहां इंसानों से ज्यादा सुअर रहते हैं। इस द्वीप की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां के सुअर समुद्र में तैरते नजर आते हैं। यही वजह है कि दुनियाभर से हजारों टूरिस्ट सिर्फ इन रिवॉमिंग पिग्ग्स को देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। नीले समंदर के बीच बसे इस छोटे से आइलैंड पर सुअरों की बड़ी आबादी रहती है। पर्यटक नावों के जरिए यहां पहुंचते हैं और सुअरों के साथ पानी में उतरकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। कई लोग इन्हें खाना खिलाते हैं, जबकि कुछ टूरिस्ट मस्ती-मजाक में इन्हें हिंसक तक ऑफर करते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर इस जगह के वीडियो और तस्वीरें अक्सर वायरल होते रहते हैं। हालांकि, सबसे चढ़ा सवाल यह है कि आखिर इस निर्जन आइलैंड पर इतने सारे सुअर आए कहां से? इसे लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। एक कहानी के अनुसार, सालों पहले कुछ नाविक लंबी समुद्री यात्रा पर निकले थे। उन्होंने रास्ते में खाने के लिए सुअरों को इस द्वीप पर छोड़ दिया था, ताकि लौटने पर उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन, वे नाविक कभी वापस नहीं आए और सुअर यहीं बस गए।वहीं, दूसरी कहानी यह बताती है कि कई दशक पहले इस इलाके के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उस जहाज से कुछ सुअर बचकर तैरते हुए इस द्वीप तक पहुंच गए। बाद में प्रजनन के कारण इनकी संख्या तेजी से बढ़ती चली गई और पूरा आइलैंड इनका घर बन गया। टूरिस्टों के लिए यह जगह किसी रोमांच से कम नहीं है। समुद्र में तैरते सुअरों को देखना लोगों के लिए बेहद अनोखा अनुभव माना जाता है। लेकिन, दूसरी तरफ एनिमल एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार इंसानी संपर्क और गलत खानपान इन जानवरों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कई बार टूरिस्ट बोट्स से सुअरों को चोट भी लग जाती है।कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि यहां सात सुअरों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि उन्होंने बड़ी मात्रा में रेत निगल ली थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसके अलावा तेज धूप और गर्म रेत भी इनके स्वास्थ्य पर असर डालती है।

सावधानी बरतने की जरूरत हालांकि, ये सुअर अब इंसानों के बीच काफी सहज नजर आते हैं, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि वे पूरी तरह जंगली हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

हमारा ब्रह्मांड अपने भीतर कई राज छिपाए हुए हैं। दुनियाभर के वैज्ञानिक आए दिन इसमें कुछ न कुछ नया खोजते रहते हैं। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्रह्मांड के पास सबसे ज्यादा स्टडी की गई गैलक्सी मर्जर्स में से एक, एंटेना गैलक्सी के अंदर पहले से छिपे एक विशालकाय ब्लैक होल के सबूत का पता लगाया है।

वॉशिंगटन। रिसर्च के निष्कर्षों से पता चलता है कि मर्ज हो रही गैलक्सी एनजीसी 4039 के अंदर एक घनी ऊर्जा पैदा करने वाला ब्लैक होल हो सकता है, जो इंटेस स्टार फॉर्मेशन एक्टिविटी के चलते छिपा हुआ है।

इस छोटी सी हलचल ने खोला राज

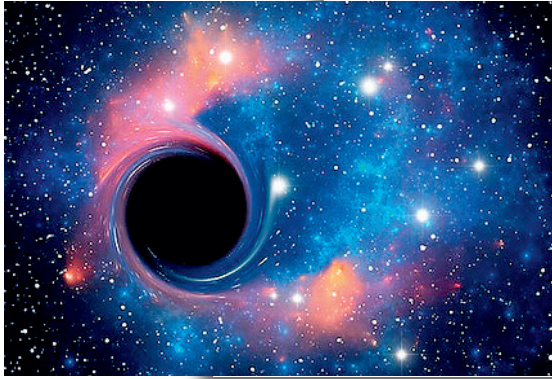


छिपा हो सकता है ब्लैक होल

गैलक्सी मर्जर गैस को गैलक्टिक सेंटर्स तक चैनल कर सकती है, जिससे सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऊर्जा मिलती है और वे एक्टिव गैलक्सी न्यूक्लाई में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि, एंटेना गैलक्सी में अबतक स्टार विस्फोट की एक्टिविटी हावी दिखाई दी है और इस बात के बेहद कम प्रमाण मिले हैं कि कोई भी सेंट्रल ब्लैक होल एक्टिवली मैटर को इकट्ठा कर रहा था। आगे की जांच के लिए जापान के 'कोगाकुइन यूनिवर्सिटी' के शिन्य कोमुगी के नेतृत्व में एक टीम ने 100 जीएचजेड पर इस सिस्टम का ऑब्जर्वेशन करने के लिए अट्टाकामा लाज मिलीमीटर/सबमिलीमीटर पेरे का इस्तेमाल किया। एक बेवसाइड के मुताबिक, रिसर्चर्स ने लगभग ढाई महीनों में 52 बार गैलक्सी की निगरानी की और उनकी चमक में होने वाले बदलावों को खोज की।

52

बार गैलक्सी की निगरानी की और उनकी चमक में होने वाले बदलावों की खोज



बर्थडे से एक दिन पहले हुई मौत!

बुखारेस्ट। यूरोप के सबसे उपद्रदाज व्यक्ति इलिए सियोकान का 113वें जन्मदिन से महज एक दिन पहले निधन हो गया। 28 मई को उनका 113वां जन्मदिन होना था, लेकिन 27 मई को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की खबर सुनकर यूरोप में शोक की लहर दौड़ गई। इलिए ना सिर्फ यूरोप के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे उपद्रदाज जीवित व्यक्ति भी थे।

इलिए सियोकान का जन्म 28 मई 1913 को रोमानिया के क्रेमेनारी गांव में हुआ था। मात्र 12 साल की उम्र में उन्होंने माता-पिता को खो दिया, इसके बाद उन्होंने गाय चराकर परिवार का पेट पाला। बड़े भाई अलियन ने परिवार की मुख्य जिम्मेदारी संभाली। जीवन की शुरुआत संघर्ष से हुई, लेकिन इलिए ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध भी देखा और कई ऐतिहासिक घटनाओं के गवाह बने।

लंबी उम्र के वैज्ञानिक कारण

वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबी उम्र के पीछे आनुवंशिक कारण, स्वस्थ भोजन, सक्रिय जीवनशैली और सकारात्मक मानसिकता होती है। इलिए का केस भी इसी को प्रमाणित करता है। उन्होंने कभी सिगरेट या शराब नहीं खुई और सादा जीवन जिया।



113 साल की उम्र में भी रहे सक्रिय

इलिए 100 साल पार करने के बाद भी काफी सक्रिय रहते थे। वे गांव के लोगों से मिलते, सलाह देते और अपनी कहानियां सुनाते थे। उनके अनुसार, जिंदगी में गुस्सा मत करो, मेहनत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। उनकी ये सीख आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। दुनिया के कई देशों से उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और अन्य संगठनों ने भी उन्हें ब्रह्मजलि दी, वे दुनिया के सबसे उमरदराज लोगों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर थे। अब उनके बाद नया नाम इस लिस्ट में शामिल होगा। रोमानिया सरकार ने इलिए को कई बार सम्मानित किया था। वे अपने गांव में लोकप्रिय थे। गांव वाले उन्हें प्यार से 'दादाजी' कहकर बुलाते थे।

सुर्खियां

नाइजीरिया में मचा हंगामा

पढ़ने-खेलने की उम्र में बना दमदार पॉलिटिशियन

अबूजा। राजनीति में अक्सर बड़े-बड़े वादे, तीखे भाषण और विवाद सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आ जाते हैं जो पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। सोचिए, अगर कोई शख्स अपनी उम्र छुपाकर चुनावी मैदान में उतर जाए और खुद को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश करे, तो क्या होगा? ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला नाइजीरिया से सामने आया, जिसने लोगों को दंग कर दिया।

यह कहानी है महमूद सादिस बाबा की, जिन्हें लोग 'अबीन अल-जान्जी' के नाम से भी जानते हैं। वह नाइजीरिया की सत्ताधारी पार्टी ऑल प्रोग्रेसिव्स कांग्रेस से जुड़े थे और अपनी लोकप्रियता के कारण द वंडर ऑफ जाेरिया कहे जाते थे। अचानक उनकी की कोशिश करे, तो क्या होगा? ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला नाइजीरिया से सामने आया, जिसने लोगों को दंग कर दिया।



महमूद ने अंततः पीछे हटने का फैसला किया

विवाद बढ़ने पर महमूद ने भी अंततः पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को एक भावुक पत्र लिखकर चुनावी दौड़ से हटने की घोषणा कर दी। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। इस तरह एक ऐसे युवक का सपना अधूरा रह गया, जो खुद को देश की राजनीति में स्थापित करना चाहता था। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने यह जरूर दिखा दिया कि राजनीति में सच कितनी जल्दी सामने आ सकता है, और झूठ ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता।

सोशल मीडिया पर सामने आने लगे दस्तावेज

लेकिन, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर उनके दस्तावेज सामने आने लगे, जिन्होंने पूरे मामले की सच्चाई उजागर कर दी। पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, महमूद का जन्म 1995 नहीं, बल्कि 2010 में हुआ था। यानी उनकी असली उम्र महज 15 या 16 साल थी, जो चुनाव लड़ने की न्यूनतम कानूनी उम्र से काफी कम है। शुरुआत में उनकी पार्टी एपीसी ने इन आरोपों की रिसे से खारिज कर दिया और इसे साजिश बताया। लेकिन, जैसे-जैसे पुष्टा सबूत सामने आते गए, पार्टी की स्थिति कमजोर पड़ती गई। आखिरकार सब सामने आने के बाद पार्टी ने उन्हें चुनाव के लिए अनौपचार घोषित कर दिया।

जहरीला पक्षी! जिसे छूने से ही जा सकती है जान

पोर्ट मोरेस्बी। दुनिया में जहरीले जीवों की बात हो तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले सांप, मकड़ी या बिच्छू का नाम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पक्षी भी मौजूद है, जिसे छूना इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? इस अनोखे और बेहद जहरीले पक्षी का नाम है हूडेड पिटोहुई। यह पक्षी मुख्य रूप से न्यू गिनी के जंगलों में पाया जाता है और इसे दुनिया का सबसे विषैला पक्षी माना जाता है।

इस पक्षी की खोज 1980 के दशक में वैज्ञानिक जैक डंबाचर ने की थी। वे न्यू गिनी में फील्डवर्क कर रहे थे, तो पक्षी उन्होंने पहली बार इस पक्षी को पकड़ा।

पक्षी को छूने के कुछ ही

देर बाद उन्हें अपने हाथों, आंखों और मुंह में तेज जलन, झुनझुनी और सुनपन महसूस होने लगा। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि इस पक्षी की त्वचा और पंख जहरीले होते हैं।

■ देखते ही दूर भागने लगते हैं इंसान

रिसर्च में हुआ खुलासा

साल 1992 में प्रकाशित एक रिसर्च में डंबाचर और उनकी टीम ने खुलासा किया कि हूडेड पिटोहुई के शरीर में बैट्राकोटीक्सिन नाम का खतरनाक जहर पाया जाता है। यही जहर कुछ बेहद जहरीले मेंढकों में भी मिलता है। यह टॉक्सिन पक्षी को शिकारियों और परजीवियों से बचाने में मदद करता है। अगर कोई शिकारी इसे खाने की कोशिश करे, तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह पक्षी खुद अपने शरीर में जहर नहीं बनाता, वैज्ञानिकों के अनुसार, हूडेड पिटोहुई अपनी डाइट से यह जहर हासिल करता है। यह मैलिरिड बीटल्स नाम के जहरीले कीड़ों को खाता है, जिनमें बैट्राकोटीक्सिन मौजूद होता है। बाद में पक्षी की त्वचा और पंखों में जमा हो जाता है। यही जहर पक्षी की त्वचा और पंखों में जमा हो जाता है।

लोग इस पक्षी से दूरी बनाकर रखते हैं

इस पक्षी के चमकोले काले और नारंगी रंग भी खास मकसद पूरा करते हैं। इसे अपोसेमेटिज्म कहा जाता है, यानी ऐसा रंग जो दूसरे जीवों को चेतावनी देता है कि यह खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि न्यू गिनी के स्थानीय लोग इस पक्षी से दूरी बनाकर रखते हैं। वहां के लोग इसे रबिशा बर्ड यानी बेकार पक्षी भी कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में ऐसे पक्षी बेहद कम हैं, जो आत्मरक्षा के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं।



वेहरे की चर्बी घटायें

वेहरे की झुर्रियां व चर्बी का वैजर द्वारा ईलाज

डॉ. ज. शासन से मान्यता प्राप्त

कालाड़ा हर्न एंव प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर

आर.के.सी.के.समन, चौबे कालोनी एवं पंचपेठ नाला, धमरवी रोड, कलर्स मॉल के पास, रायपुर नाक : 9827143060/8871003060

9827143060